



2026:AHC-LKO:21964

इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ**लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2200 वर्ष 2026**

शिवम द्विवेदी उर्फ के.डी

.....आवेदक(कों)

बनाम

मुख्य सचिव (गृह) के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, लखनऊ।

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: शील निधि शुक्ला, प्रिया मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या.-18**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अध्ययन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियोजन पक्ष के मामले में आरोप लगाया गया है कि 27.03.2024 को रात लगभग 9:00 बजे, शिकायतकर्ता के भाई ज्ञान प्रकाश को शुभम पांडे, के.डी. और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने आनंद विहार कॉलोनी, पुलिस स्टेशन पारा में बुलाया। आगे आरोप है कि वहां पहुंचने पर उक्त व्यक्तियों ने उन पर बेरहमी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में उन्हें ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसमें दो मामले शामिल हैं, जमानत आवेदन के अनुच्छेद 26 में विधिवत स्पष्ट किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक 13.12.2024 से न्यायिक हिरासत में है। अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने दो नामजद और दो बेनाम आरोपियों के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए हैं, किसी भी आरोपी की भूमिका स्पष्ट नहीं की है। विशेष रूप से, यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों में से किसने घायल को जानलेवा चोट पहुंचाई है।

यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि कथित घटना 27.03.2024 को हुई थी, लेकिन घायल को आपातकालीन वार्ड में केवल 30 मार्च 2024 को तीन दिन की देरी के बाद भर्ती कराया गया था।, विद्वान अधिवक्ता ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि चोटें वास्तव में इतनी गंभीर थीं, तो यह बात समझ से परे है कि घायल व्यक्ति ने तुरंत चिकित्सा सहायता क्यों नहीं ली। उन्होंने यह भी कहा कि घायल व्यक्ति की कोई प्रारंभिक चिकित्सा-कानूनी जांच नहीं की गई थी।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि यद्यपि घटना 27.03.2024 को घटी बताई जा रही है, लेकिन जांच अधिकारी ने आवेदक को काफी समय बाद, यानी 13.12.2024 को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हिरासत में लिया। न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और 30.03.2024 की मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया है कि यद्यपि घटना स्थल कई घरों वाले एक आवासीय क्षेत्र में स्थित है, फिर भी जांच अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज नहीं किए हैं।

इसके अलावा यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के जेल से रिहा होने के बाद भाग जाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा बताए जाने पर एक लोहे की छड़ बरामद की गई है, जो उसे कथित अपराध से जोड़ती है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर उचित विचार करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि इस मामले में कोई पहचान परीक्षण परेड आयोजित नहीं की गई है। इसके अलावा, इस स्तर पर, कथित घटना की तिथि, यानी 27.03.2024, और घायल को 30.03.2024 को आपातकालीन वार्ड में भर्ती किए जाने के बीच की देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय यह पाता है कि यह मामला आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त है।

अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है। आरोपी शिवम द्विवेदी उर्फ के.डी. को अपराध संख्या 164/2024, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/506/326 के तहत, पारा पुलिस स्टेशन,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिला लखनऊ में दर्ज मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा।

मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, निचली अदालत/संबंधित अदालत द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत याचिका तक ही सीमित हैं और मुकदमे की खूबियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28 मार्च, 2026

आर.सी.

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।